

# वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की “नो फर्स्ट यूज” नीति की प्रासंगिकता

## Relevance of India's "No First Use" policy in the present context

Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance: 23/11/2021, Date of Publication: 24/11/2021

### सारांश

स्वतंत्रता के पश्चात् 1947 से ही भारत परमाणु बम न बनाने के संकल्प पर दृढ़ रहा है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण विभिन्न नेतृत्वों का दृष्टिकोण भी बदलता रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू परमाणु के सैन्य उपयोग के पक्षधर नहीं थे अतः आरम्भ में परमाणु कार्यक्रम को मात्र असैन्य उपयोग तक ही सीमित रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् धीरे-धीरे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस तथा फ्रांस ने परमाणु शक्ति ग्रहण कर ली। वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध, वर्ष 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण तथा वर्ष 1965 में पाकिस्तान से युद्ध आदि घटनाक्रम के पश्चात् भारत को अपनी नीति में परिवर्तन के लिए विवश होना पड़ा। इस नीति में बदलाव के साथ भारत ने पोखरण में वर्ष 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण तथा 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया। इन परीक्षणों के कारण विश्व समुदाय ने भारत पर कई तरह के प्रतिबन्ध लगाये। इस कारण भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार देश सिद्ध करते हुए 1998 में आठ सूत्री परमाणु नीति की घोषणा करते हुए अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के विरुद्ध “पहले उपयोग नहीं” (नो फर्स्ट यूज) की घोषणा की इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु आक्रमण तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर देता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के पाकिस्तान से चल रहे तनाव को लेकर भविष्य में “नो फर्स्ट यूज” पॉलिसी में भारत द्वारा परिवर्तन के संकेत दिए गए हैं।

तनुश्री शर्मा  
शोधार्थी,  
राजनीति विज्ञान  
विभाग,  
राजस्थान विश्व विद्यालय  
जयपुर, राजस्थान, भारत

After independence, since 1947, India has remained firm on its resolve not to make atomic bombs. But due to the international environment, national interest and national security, the attitude of various leaders has also been changing. India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru was not in favor of the military use of nuclear, so initially the nuclear program was restricted to civilian use only. After the Second World War, America, Britain, Russia and France gradually assumed nuclear power. After the war with China in the year 1962, the nuclear test by China in the year 1964 and the war with Pakistan in the year 1965, India was forced to change its policy. With this change in policy, India conducted the first nuclear test in Pokhran in 1974 and the second nuclear test in 1998. Due to these tests, the world community imposed many restrictions on India. For this reason, India, proving itself a responsible country, announced the eight-point nuclear policy in 1998, according to this policy of declaring its nuclear weapons "no first use" against any country. Nuclear attack on any country will not happen until the enemy country does not attack on India. In the present context, India has indicated a change in the "No First Use" policy in the future regarding the ongoing tension with Pakistan.

**मुख्य शब्दः-** राष्ट्रीय हित, पोकरण परीक्षण, प्रतिबन्ध, जिम्मेदार देश, नो फर्स्ट यूज नीति,

**Keywords:** National interest, Pokhran test, Ban, Responsible country, No first use policy,

### प्रस्तावना

भारत साधारण और सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण का दृढ़ और पक्का समर्थक रहा है और वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में सर्वोच्च प्राथमिकता से जुड़ा हुआ है। निःशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक एवम् मानवीय संसाधनों का उन्मूलन करना है यह एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को हल करना है। निःशस्त्रीकरण के संबंध में भारत की नीति में विशेषतः 1990 में दशक में आए विश्व व्यापी परिवर्तनों को भी ध्यान रखा गया है। मई 1998 के परमाणु परीक्षण से लम्बे समय से चले आ रहे इस उद्देश्य के प्रति भारत की वचनबद्धता कमजोर नहीं पड़ती है। यह दिशा इस देश को अन्य परमाणु हथियारों वाले देशों से पृथक् करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं क्योंकि वे परमाणु हथियारों के बिना स्वसुरक्षा की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश होने के नाते भारत इस

संबंध में अपने उत्तरदायित्व के प्रति और अधिक सजग है और पूर्ववत् भारत अपने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में निरंतर पहल करता रहेगा। भारत की परमाणु हथियार क्षमता का अभिप्राय मात्र आत्मरक्षा है और इससे यह भी सुनिश्चित करना है कि भारत की सुरक्षा स्वतंत्रता और अखण्डता को भविष्य में कोई खतरा न हो भारत की परमाणु नीति न्यूनतम भय से मुक्ति और अपनी ओर से पहले उपयोग न करना जैसे दो स्तम्भ इसके मूलाधार हैं। भारत की विदेश नीति के मूलभूत तीन उद्देश्यों राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक विकास एवं विश्व व्यवस्था के साथ-साथ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद का विरोध करते हुए परस्पर सहअस्तित्व एवं सभी राष्ट्र में मित्रता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सद्भाव उत्पन्न करना है भारत ने 2019 में अपनी परमाणु नीति “नो फर्स्ट यूज” (प्रथम रूप से प्रयोग न करने की नीति) के वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के संकेत दिए हैं किन्तु भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य अपनी सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करते हुए एक ऐसे विश्व की स्थापना करना है जो सहयोग, सद्भाव एवं शान्ति पर आधारित हो इस शोध में भारत की परमाणु नीति “नो फर्स्ट यूज” का वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता के रूप में अध्ययन किया जाएगा।

### अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत की परमाणु नीति का सैद्धान्तिक विश्लेषण करना।
2. भारत की परमाणु नीति के सिद्धान्तों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
3. वर्तमान समय में भारत के समक्ष आ रही सुरक्षात्मक चुनौतियों का अध्ययन करना।
4. भारत के पड़ोसी राष्ट्रों एवं क्षेत्रीय राजनीति के साथ हिन्द महासागर में उभर रही नवीन चुनौतियों के सन्दर्भ में भारत की परमाणु नीति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
5. अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण में भारत की बढ़ती भूमिका का विवेचन करना।

### अध्ययन क्षेत्र का परिचय

1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु शक्ति के उपयोग के क्षेत्र में भारतीय नीति में व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर के अमेरिका के दबाव की उपेक्षा करते हुए भारत ने 11 मई एवं 13 मई 1998 को पोकरण में एक हाइड्रोजन बम सहित पांच परमाणु बमों की परीक्षण करके विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान द्वारा प्रतिक्रियास्वरूप छः परमाणु परीक्षण करने के कारण भारत को अपनी परमाणु नीति में अनिवार्य रूप से परिवर्तन करने हेतु बाध्य होना पड़ा। इस प्रतिद्वंद्वितापूर्ण विस्फोट ने भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन एवं शान्ति व्यवस्था को अत्यन्त प्रभावित किया। भारत अपने लिए परमाणु आक्रमण का खतरा महसूस करने लगा। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री को अपने देशकी जनता के समक्ष दो नीतियां स्पष्ट करनी पड़ी प्रथम नीति नो फर्स्ट यूज अर्थात् भारत परमाणु आक्रमण को कभी स्वयं से प्रारम्भ नहीं करेगा तथा द्वितीय परमाणु आक्रमण का भारत प्रतिक्रियात्मक रूप से उत्तर देगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के पश्चात् पाकिस्तान से चल रहे तनाव को लेकर भविष्य में वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के संकेत दिए हैं। इस शोध में भारतीय परमाणु नीति को नवीन दिशा दी गई है।

### विषय वस्तु

पहले प्रयोग न करने की नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शीत युद्ध के दिनों में निहित है। तत्कालीन समय यूरोप के भीतर पारम्परिक सैन्य शक्ति में वारसा संधि को बड़ी बढत प्राप्त थी। उस समय नाटो ने सोवियत संघ के आक्रमण के दौरान पश्चिमी यूरोप को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में परमाणु हथियार के प्रथम रूप से प्रयोग करने के विकल्प को खुला रखा था किन्तु सोवियत संघ की सेना जिसे पारम्परिक संघर्ष में बढत प्राप्त थी। उसने सन् 1983 में प्रथम रूप से प्रयोग न करने की नीति ग्रहण कर ली। इसी प्रकार भारत को भी पाकिस्तान पर पारम्परिक बढत प्राप्त होने के कारण भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनायी है। इस शोध में निम्न परिकल्पनाओं का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है।

1. विश्व के विभिन्न देशों के मध्य परमाणु परीक्षण प्रतिस्पर्धा के कारण शक्ति संतुलन एवं भय का संतुलन कायम हुआ है।
2. भय एवं असुरक्षा के कारण वर्तमान में विश्व में परमाणु शस्त्रों की होड लगी है।
3. भारत की परमाणु नीति सम्पूर्ण विश्व में सराहनीय है।
4. भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति देश की शान्ति एवं स्थायित्व को सुनिश्चित करती है।
5. भारत की परमाणु नीति की उत्पत्ति गांधीवादी परम्परा एवं अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित है।

### भारत की “नो फर्स्ट यूज” नीति

1. भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धान्त प्रथम रूप से प्रयोग नहीं है जो भारत को विश्व के अन्य देशों से भिन्न बनाता है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु आक्रमण तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करता है।
2. भारत परमाणु नीति को इतना सुदृढ रखेगा कि शत्रु देश के मन में आतंक बना रहे।

3. शत्रु देश के विरुद्ध परमाणु आक्रमण की कार्यवाही करने का अधिकार केवल जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात् देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा।
4. जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं उन देशों के विरुद्ध भारत अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा।
5. यदि भारत के विरुद्ध या भारतीय सुरक्षा बलों के विरुद्ध कोई रासायनिक जैविक आक्रमण होता है तो भारत इसके प्रत्युत्तर में परमाणु आक्रमण विकल्प खुला रखेगा।
6. भारत परमाणु मुक्त विश्व निर्माण की वैश्विक पहल का समर्थन करता रहेगा तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निःशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा।

#### वर्तमान में “नो फर्स्ट यूज” नीति की प्रासंगिकता

1. भारत के दो प्रमुख पड़ोसी पाकिस्तान और चीन परमाणुशक्ति सम्पन्न देश हैं।
2. परमाणु शक्ति सम्पन्न उत्तर कोरिया और रूस भी भारतसे अधिक दूर नहीं हैं।
3. नो फर्स्ट यूज नीति हमारे परमाणु कार्यक्रम के आत्मरक्षात्मक होने का समर्थन करती है।
4. यह नीति बताती है कि भारत एक जिम्मेदार एवं जवाबदेह परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है।
5. इस नीति से भारत के परमाणु कार्यक्रम की अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन भारत का समर्थन कर रहे हैं।

#### निष्कर्ष

इस प्रकार इस शोध से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत की अमेरिका से समीपता रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्ते और दक्षिण पश्चिम एशिया में देशों के साथ सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो रहे रिश्तों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि भारत के द्वारा परमाणु नीति में परिवर्तन किया जाता है तो ये देशकिसी भी तरह की असहमति व्यक्त नहीं करेंगे लेकिन आगामी अवधि में भारत को इससे क्षति हो सकती है। भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश पाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। ऐसे में नीति में अकस्मात् परिवर्तन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यह उचित है कि प्रत्येक नीति की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन भी करना चाहिए परन्तु यह परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में न आकर राष्ट्रीय हित के अनुरूप होना चाहिए।

भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान परमाणु सम्पन्न देश स्थित हैं चीन की पूर्व से यही नीति है कि वह केवल प्रतिकार में ही आण्विक अस्त्रों का प्रयोग करेगा प्रथम रूप से कदापि प्रयोग नहीं करेगा इसलिए यदि भारत अपनी नीति में परिवर्तन करता है तो संभव है कि चीन इसका लाभ उठाकर अमेरिका रूस एवं भारत के प्रति प्रथम रूप से प्रयोग कर आक्रमण कर दे और इसका आरोप भारत की परिवर्तित नीति पर लगा दे। भारत सदैव स्वयं को एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति सम्पन्न देशके रूप में विश्व के समक्ष रखता आया है अतः भारत के फर्स्ट यूज की नीति अपनाने से भारत की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत की वर्तमान नीति के कारण ही भारत और पाकिस्तान अपने-अपने परमाणु शस्त्रों को युद्ध स्तर पर सुसज्जित नहीं रखते हैं। इस कारण पाकिस्तान में आण्विक आतंकवाद की सम्भावना कम रहती है। इस प्रकार नो फर्स्ट यूज की नीति शान्तिकाल का आश्वासन है जो किसी देशकी शान्ति और स्थायित्व सुनिश्चित करने की उत्तरदायी प्रकृति को दर्शाती है। अतः भारत को शान्तिकाल और युद्धकाल दोनों के लिए दो भिन्न-भिन्न परमाणु हथियार निर्मित करने और चीन द्वारा त्वरित सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार करने के कारण युद्धकाल हेतु भिन्न परमाणु नीति का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र, सुरेन्द्र कुमार, “ भारतीय परमाणु नीति, निःशस्त्रीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा” राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2006, पृ. 164
2. सिंह जयजीत “ भारतीय परमाणु शस्त्र” प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2003, पृ. 184
3. द हिन्दू, दिल्ली, 17 अगस्त 2019
4. प्रतियोगिता दर्पण 2019
5. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/No\\_First\\_Use#](https://en.m.wikipedia.org/wiki/No_First_Use#)
6. यादव, आर.एस., “भारत की विदेशनीति: एक विश्लेषण” 2004, किताबमहल डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ. 428
7. इन्दा उम्मेद सिंह एवं जाखड अरुण, “भारतीय परमाणु नीति: वर्तमान चुनौतियाँ” 2014, आ.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, पृ. 61
8. राजस्थान पत्रिका, जयपुर, सितम्बर, 2019
9. दैनिक जागरण, दिल्ली, जनवरी, 2020